उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

25 अप्रैल, 2018 • वर्ष 1, अंक 14

सात दिन – सात पृष्ठ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
जनपद प्रतापगढ़ भ्रमण के दौरान महुली मण्डी गेहूँ क्रय केन्द्र का निरीक्षण किया

- मुख्यमंत्री जी ने प्रतापगढ़ में लगाई रात्रि चौपाल
- फेसबुक पर सर्वाधिक पसंदीदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
- किसानों का मिल रहा है उपज का सही दाम
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 25 लाख तक लोन
- सूखा प्रभावित परिवारों की सहायता
- 3.10 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री जी ने प्रतापगढ़ में ग्रामीणों के साथ लगाई चौपाल

बेहतर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर जोर

जनपद प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था और विकास कार्यो की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि सर्वोत्तम कानून–व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने दिए ये निर्देश

- वरिष्ठ अधिकारी थानों में उपस्थित रहकर स्वयं अपराध नियंत्रण के संबंध में प्रस्तुत आंकड़ों की निगरानी करेंगे।
- थानाध्यक्ष अनिवार्य रूप से थाने के परिसर में ही निवास करेंगे तथा दागी अधिकारियों को किसी भी थाने का प्रभार किसी भी हाल में नहीं दिया जायेगा।
- जनता से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को रोकने का पूरा उत्तरदायित्व पुलिस एवं जिला प्रशासन का होगा।
- ऐन्टी रोमियो अभियान को अधिक सशक्त बनाया जायेगा और विमेन पावर लाइन '1090' का और प्रभावी संचालन होगा।
- सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाएगी तथा इस संबंध में शिकायतों के निस्तारण हेतु टॉल फ्री नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रतापगढ़ के कंधई माधोपुर गांव में रात्रि चौपाल लगाकर जनता से स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जाना विकास योजनाओं का हाल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मानना है सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं से जनता को कितना लाभ मिल रहा है, इस बात की सच्चाई जानने के लिए आम जनता के बीच जाकर उनसे संवाद कायम करना ही सर्वोत्तम तरीका है। आम जनता और सरकार के बीच संवाद को परस्पर मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी ने जनपद प्रतापगढ़ के कंधई माधोपुर गांव में रात्रि चौपाल लगवाकर ग्रामीणों से उन्हें दी जा रही सरकारी सुविधाओं के लाभ के विषय में चर्चा की।

दलालों को रोककर सीधे जनता को लाभ दिलाना है उद्देश्य

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं सचालित की जा रही हैं, लेकिन आम जन को योजनाओं की सही जानकारी न होने के कारण बिचौलिये तथा दलाल सक्रिय हो जाते हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए सरकार स्वयं जनता को योजनाओं की सही तथा सटीक जानकारी प्रदान करना चाहती है ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरा फायदा संबंधित वर्ग को मिल सके।

बच्चों का अन्नप्राशन तथा महिलाओं की गोदभराई

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने तीन महिलाओं की गोदभराई तथा पॉच बच्चों के अन्नप्राशन की रस्म पूरी की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवास की चाभी सौंपी और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन के कागज भी सौंपे। मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर उपस्थित जनसमूह अत्यन्त प्रफुल्लित था और सबने एक स्वर में कहा कि मुख्यमंत्री जी जनता के दुःख दर्द को भलीभांति समझते हैं और उसे दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

तेजी से कम हो रहे हैं बालू मौरंग के दाम

निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु योगी सरकार ने गंभीरता से कार्य करते हुए बालू और मौरंग की ओवरलोडिंग में 30 फीसदी की छूट दे दी है, जिससे बाजार में बालू और मौरंग की दाम पहले की तुलना में कम हुए हैं। लेकिन सरकार इन दामों को और कम करने के लिए प्रयासरत है। अब पर्यावरण विभाग द्वारा स्टेट लेविल एनवॉयरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास खनन पट्टों से होने वाले पर्यावरणीय असर की एनओसी निर्गत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है, जिससे इस पूरी प्रक्रिया में समय कम लगेगा और पट्टे आवंटन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस प्रकार प्रदेश में सस्ती बालू और मौरंग आसानी से उपलब्ध होगी।

किसानों का मिल रहा है उपज का सही दाम

शाहजहांपुर गेहूं की खरीद के मामले में पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है परन्तु वहां से मिली कतिपय शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं जनपद शाहजहांपुर पहुंचकर गेहूं क्रय केन्द्रों और गन्ना क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने गेहूं खरीद को लेकर किसानों से जानकारी ली और उनकी परेशानियां पूछीं। उन्होंने किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।

निर्धारित मूल्य के अनुसार होगी गेहूं की खरीद

गेहूं क्रय हेतु सरकार द्वारा 1,735 रुपये का मूल्य निर्धारित किया गया है और केन्द्रों पर किसानों से निर्धारित मूल्य के अनुसार ही गेहूं खरीदा जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसे लेकर उन्हें किसी प्रकार की समस्या न होने पाये, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उच्चाधिकारियों को गेहूं क्रय केन्द्रों का समय–समय पर निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए गये हैं।

किसानों को सीधे खाते में मिल रही है धनराशि

सरकार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है और धनराशि सही व्यक्ति को ही मिले इसका भी पूरा ध्यान रख रही है। इसलिए गेहूं क्रय केन्द्र पर जिन कृषकों से खरीद की गयी है, उनका सत्यापन कराया जायेगा ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। उपज मूल्य का भुगतान सीधे कृषकों के खातों में किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने जनपद शाहजहांपुर में गेहूं और गन्ना क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर दिए उपज की खरीद और भुगतान के सत्यापन के निर्देश

सरकार की प्राथमिकता हैं किसान

सरकार की प्राथमिकता किसान हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है कि अगर किसानों के भुगतान में किसी भी तरह की कोई अनियमितता पाई गयी तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी। किसानों के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। ■

खास खबर

फेसबुक पर सर्वाधिक पसंदीदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के फेसबुक पेज को मिले सर्वाधिक 54,68,300 लाइक्स

सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफार्म फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देश के सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे आगे रहे हैं। उनके फेसबुक पेज को देश में सर्वाधिक लोगों ने लाइक और शेयर किया है। फेसबुक के अनुसार एक जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 के दौरान अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पेज पर मिले लाइकिंग और शेयर के आधार पर निकाले गये निष्कर्षों में योगी आदित्यनाथ जी टॉप पर रहे है। दूसरे स्थान पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी रही हैं जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी को इस लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल हुआ है।

सूखा प्रभावित परिवारों की सहायता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सूखा प्रभावित परिवारों की सहायता हेतु कृत संकल्पित हैं। उनके निर्देशानुसार प्रदेश में सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को जीवन यापन हेतु खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

5 सूखाग्रस्त जिलों में होगा वितरण

खाद्य सामग्री का वितरण प्रदेश के पांच जिलों की सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों तथा ग्रामों में किया जायेगा। योजना का लाभ उन सभी परिवारों को मिलेगा, जो अंत्योदय लाभार्थी हों तथा जिनकी आजीविका सूखे के कारण प्रभावित हुई हो।

1 से 31 मई तक होगा पहला चरण

प्रदेश सरकार द्वारा महोबा जनपद की महोबा, चरखारी तथा कुलपहाड़, सोनभद्र जनपद की घोरावल, दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज, झांसी जनपद की गरौठा तथा मऊरानीपुर और मीरजापुर की मड़िहान तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसके अलावा जनपद ललितपुर के 12 ग्रामों, झांसी की झांसी तहसील के 27 गांव तथा टहरौली के 49 गांवों को भी सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इस सभी में राहत सामग्री का वितरण किया जायेगा। प्रारम्भिक चरण में यह योजना 1 से 31 मई तक संचालित की जायेगी।

कैम्प लगाकर होगा वितरण

राहत सामग्री के वितरण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा राहत समिति द्वारा राहत सामग्री का क्रय किया जायेगा। सामग्री का वितरण ग्राम स्तर पर कैम्प लगाकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जायेगा।

दर्ज होगा हर लाभार्थी का विवरण

जिन सूखा प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री का वितरण होगा, उन सभी के पते तथा मोबाइल नंबर का विवरण जिला स्तर पर रखा जायेगा और राहत सामग्री वितरण कार्य की प्रगति की जानकारी प्रतिदिन राहत आयुक्त कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

इस प्रक्रिया से वितरण कार्य में पारदर्शिता आएगी तथा सूखे से प्रभावित वास्तविक परिवारों तक राहत सामग्री पहुंच सकेगी। ■

हर परिवार को मिलेगी इतनी खाद्य सामग्री

प्रत्येक प्रभावित परिवार को 25 किलोग्राम आटा, 25 किलोग्राम आलू, पांच किलोग्राम चने की दाल, तीन लीटर सरसों का तेल, एक किलोग्राम शुद्ध देशी घी, एक किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक तथा बच्चों के लिए प्रति परिवार एक किलोग्राम मिल्क पाउडर वितरित किया जायेगा। इस सामग्री से एक परिवार के लगभग 15 दिन तक के जीवन यापन की व्यवस्था हो सकेगी।

ऑनलाइन होगा लकड़ी उद्योगों का नवीनीकरण

प्रदेश में आरा मशीनों, प्लाईवुड यूनिट्स, सनमाइका यूनिट्स तथा बेस यूनिट्स के व्यवसाय से कई कामगार जुड़े हैं तथा प्रदेश के आर्थिक विकास में लकड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु इस क्षेत्र में लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया काफी जटिल थी और लोगों को इधर–उधर भटकना पड़ता था। अब प्रदेश सरकार ने सहूलियत प्रदान करते हुए लकड़ी उद्योगों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया सरल तथा ऑनलाइन कर दी है। अब लाइसेंस पाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा और आसान सी प्रक्रिया को पूरा करने के उपरान्त लाइसेंस मिल सकेगा। लाइसेंस नवीनीकरण के अलावा नाम परिवर्तन तथा स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। इसके लिए एक अलग वेबपोर्टल विकयिसत कराया गया है। इस पोर्टल का लिंक वन विभाग की वेबसाइट http://upforest.gov.in पर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदनकर्ता घर बैठे ही लाइसेंस नवीनीकरण अथवा अन्य कार्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मिलेगा 25 लाख तक लोन

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** शुरू की है। इस योजना के तहत इच्छुक बेरोजगार युवक/युवतियॉ उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र की इकाई यथा कम्प्यूटर सेंटर, टेंट हाउस आदि खोलने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं।

पात्रता हेतु आवश्यक योग्यताएं

लोन लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल तथा अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीय बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिन मनी अनुदान का लाभ न लिया हो। लोन प्राप्त करने में कम परियोजना लागत की इकाइयों को प्राथमिकता दी जायेगी।

28 अप्रैल से 26 मई तक करना होगा आवेदन

लोन लेने के इच्छुक आवेदकों को 28 अप्रैल से 26 मई तक किसी भी कार्यदिवस में सूचनाएं एवं आवेदन–पत्र प्राप्त व जमा कर सकते हैं।

मुद्रा योजना में 10 हजार लोगों को मिलेगा लोन

प्रदेश सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रयत्नशील है। निवेशकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश के उत्पादों को नई दिशा मिलेगी। इसलिए सरकार द्वारा निवेश मित्र योजना का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि उद्यमियों को इसके बारे में विधिवत जानकारी हो सके। उनकी समस्याओं का समाधान निवेश मित्र के तहत निश्चित समय में किया जायेगा।

प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। सरकार ने मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा अन्य रोजगारपरक योजनाओं के तहत आगामी चार वर्षों में 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इन योजनाओं के तहत एक वर्ष में पांच लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जायेगा।

स्वरोजगार के नये अवसरों का सृजन

प्रदेश सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत 27 मई, 2018 को 10 हजार लोगों को उद्यम स्थापना के लिए ऋण प्रदान किया जायेगा। इससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा और प्रदेश में लघु उद्योगों की बेहतरी का मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रत्येक जिले में ऋण शिविरों का आयोजन किया जायेगा और कम से कम 1000 लोगों को प्रतिमाह रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। ■

सभी नागर निकायों में सेप्टेज उपचार के लिए स्थापित होंगे एसटीपी

बढ़ती जनसंख्या एवं अन्य गतिविधियों के कारण प्रदूषण एवं भू-जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे स्वास्थय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। इस आसन्न खतरे को भांपते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्य योजना बनायी जा रही है।

इसके अंतर्गत सभी नागर निकायों में सेप्टेज उपचार सुविधा हेतु एसटीपी की स्थापना की जायेगी। शहरों में पूर्ण स्वच्छता का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ठोस कचरे, सिवेज, सेप्टेज, जल निकासी के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में सेप्टेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समुचित निस्तारण, उपचार हेतु प्रदेश के शहरों द्वारा विश्वस्तर मानकों को अपनाने पर जोर दिया जायेगा क्योंकि गंदगी से विभिन्न बीमारियां पैदा होती हैं। इसके अलावा जनस्वास्थ्य के खतरों को ध्यान में रखते हुए सेप्टेज एवं मल अपशिष्ट प्रबंधन को सभी शहरों में प्राथमिकता के आधार पर अपनाया जायेगा।

शहरों को साफ-सुथरा बनाये रखने के लिए कार्य योजना बनाकर प्रभावीढंग से क्रियान्वित की जायेगी। दिसम्बर 2018 से पूर्व गंगा को अविरल एवं निर्मल बनाने के लिए बिना ट्रीटमेंट के कोई भी पानी गंगा में नहीं बहने दिया जायेगा। महाकुम्भ से पूर्व गंगा को प्रदूषणमुक्त एवं निर्मल बनाने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।

उज्ज्वला दिवस पर 3.10 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन

निर्धन परिवारों को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाने और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए संचालित उज्ज्वला योजना से भारी मात्रा में गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला दिवस मनाते हुए 3.10 लाख से अधिक परिवारों को शिविर लगाकर निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये गये।

मुफ्त गैस कनेक्शन पाकर खिल उठे चेहरे

ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत लगाये गये इन शिविरों में जनप्रतिनिधियों द्वारा गैस कनेक्शन प्रदान किये गये। शिविरों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लाभार्थियों की बढ़ी संख्या रही। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बीपीएल कार्डधारक, वनवासी, अति पिछड़े वर्ग तथा नदी की कटान से प्रभावित परिवारों को भी कनेक्शन दिये गये। प्रदेश के सभी जिलों में चिन्हित किये गये ग्रामों में इन शिविरों को आयोजन किया गया और प्रत्येक शिविर में औसतन 100 से अधिक कनेक्शन वितरित कियो गये। मुफ्त गैस कनेक्शन पाकर इन परिवारों के चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई। लाभान्वित महिलाओं ने कहा कि लकड़ी के धुएं से निजात दिलाकर सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है।

परित्यक्त नवजातों के लिए पालना शिशु स्वागत केन्द्र

कठिन परिस्थितियों में पाए गये परित्यक्त, नवजात शिशुओं की जीवन रक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में पालना शिशु स्वागत केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन पालना शिशु स्वागत केन्द्रों की स्थापना सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जिला एवं सिविल अस्पतालों, राजकीय बालगृहों, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण इकाइयों तथा चाइल्ड लाइन कार्यालयों में की जायेगी।

सुरक्षा के होंगे खास इंतजाम

इन केन्द्रों की स्थापना में सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखा जायेगा, ताकि कोई भी अज्ञात व्यक्ति, महिला दम्पत्ति जो अपनी पहचान सार्वजनिक न करना चाहता हो, नवजात शिशु को पालना केन्द्र में सुरक्षित रख कर वापस जा सके। इन केन्द्रों पर समूह 'ग' एवं 'ख' के कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेशन पर लगाई जायेगी तथा किसी राजपत्रित अधिकारी को इस केन्द्र का प्रभारी बनाया जायेगा। जनपद के मुख्य कार्यालयों में पालना केन्द्र के प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर डिस्प्ले किया जायेगा। प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी द्वारा इस उद्देश्य से एक हेल्पलाइन नम्बर सुनिश्चित किया जायेगा।

गरीबों को मिलेगा कैशलेस इलाज

खुली बैठक में घोषित होंगे लाभार्थियों के नाम

6 करोड़ लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

मिलेगी पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा

उत्तर प्रदेश में गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने का खाका तैयार कर लिया गया है। अब प्रदेश में गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा जल्द ही प्राप्त हो सकेगी।

गरीबों को निःशुल्क इलाज के लिए सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस का आधार लेते हुए पात्र परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इसके लिए 30 अप्रैल को पूरे प्रदेश की 59 हजार ग्राम पंचायतों में खुली बैठक करके लाभार्थियों के नामों की घोषणा की जायेगी। मई में डोर–टू–डोर अभियान चलाकर लाभार्थियों का सत्यापन घर–घर जाकर किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 18 लाख परिवार योजना के पात्र हैं। इस प्रकार लगभग 6 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। अब योजना में आधार कार्ड से लिंक करने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है।

इस योजना के लाभार्थियों को पांच लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। इस योजना में सभी सरकारी अस्पतालों और कई निजी अस्पतालों को जोड़ा जायेगा ताकि लोगों को उनके निकट ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

मनरेगा से छायेगी हरियाली

पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदेश के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब मनरेगा का समुचित उपयोग करने जा रही है। सरकार ने मनरेगा मजदूरों को उनकी अपनी जमीन पर पेड़ लगाने के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन, मुख्यमंत्री फलोद्यान तथा मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना प्रारंभ कर दी है।

मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार, जो मनरेगा कार्डधारक हैं, अपने खेत की मेड़ पर पौधरोपण करेंगे तो उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन दिया जायेगा। प्रारंभ में यह योजना तीन वर्षों के लिए होगी। योजना में परिवारों को तीन वर्षों तक अपने ही खेत में पेड़ लगाने तथा उसके संरक्षण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जायेगा।

मनरेगा मजदूरों को अपनी ही जमीन पर लगाने होंगे पेड़

पेड़ लगाने और संरक्षण करने पर मिलेगी आर्थिक सहायता

हरियाली बढ़ाने के लिए शुरू की गईं कई योजनायें

यूपी बनेगा सड़कों का स्वर्ग

प्रतिदिन 35 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य

हर दो दिन में बनेगा एक सेतु

सभी कार्य होंगे ऑनलाइन मिटेगा भ्रष्टाचार

विकास का रास्ता बेहतर सड़को और सेतुओं से होकर गुजरता है। इसलिए प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में बेहतरीन सड़को और सेतुओं के समयबद्ध निर्माण का संकल्प लिया है।

सरकार द्वारा औसतन हर दिन 25 किलोमीटर सड़क तथा दो दिन में एक सेतु के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सड़कों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का खासा ख्याल रखा जायेगा ताकि गड्ढों इत्यादि की संभावना न रहे। इसके लिए जल्द ही सड़क एम्बुलेंस व्यवस्था प्रारंभ की जायेगी।

अब सड़कों और सेतुओं के निर्माण का कार्य पूरे वर्ष निरंतर जारी रहेगा। सड़क निर्माण के साथ ही ड्रेनेज व्यवस्था कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सीमावर्ती सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसे 54 इंटर स्टेट मार्गों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें पड़ोसी राज्यों की सड़कों से बेहतर बनाया जायेगा।

सड़के टूटने की जानकारी मिलते ही तत्काल मरम्मत करा दी जायेगी। 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व ग्रामों को सपर्क मार्गों से जोड़ा जायेगा और गांवों में दो लेन सड़कों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

24 अप्रैल 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

पीसीएस में इंटरव्यू हुआ 100 अंको का

पीसीएस के इंटरव्यू में पारदर्शिता को बढ़ावा देनें के लिए कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 200 अंकों के इंटरव्यू को घटाकर केवल 100 अंकों का कर दिया है। लिखित परीक्षा पूर्व की ही भांति 1500 अंकों की रहेगी। इसके अलावा वैकल्पिक विषयों की संख्या दो से घटाकर केवल एक कर दी गई है। सामान्य अध्ययन के दो के स्थान पर चार पेपर होंगे। इसके अतिरिक्त परीक्षा में चिकित्सा विज्ञान को भी वैकल्पिक पेपर के तौर पर सम्मिलित किया गया है।

सरकार के इस फैसले से पीसीएस चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू का वेटेज घटेगा और लिखित परीक्षा का वेटेज बढ़ेगा, जिससे साक्षात्कार की भूमिका केवल व्यक्तित्व परीक्षण तक ही रह जाएगी।

नि:शुल्क होगा पशुओं का बधियाकरण, लेवी शुल्क हुआ समाप्त

सोशल मीडिया पर लाइव होंगे मुख्यमंत्री जी और सरकार के कार्यक्रम

पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास योजना लागू

नोएडा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निदेशक की आयु सीमा 70 साल हुई

इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्टल को ध्वस्त करके बनेगा बाल चिकित्सालय

शाहजहांपुर बना प्रदेश का 17वां नगर निगम

प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद को प्रदेश के 17वें नगर निगम का दर्जा प्रदान कर दिया है। शाहजहांपुर नगर निगम का गठन नगर पंचायत रोजा और शहर के सीमावर्ती 18 गांवों को मिलाकर किया गया है।

शाहजहांपुर के नगर निगम बनने से शहर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को और अधिक गति प्राप्त होगी और निकाय की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। इससे पहले सरकार द्वारा मथुरा–वृंदावन और अयोध्या को भी नगर निगम का दर्जा प्रदान किया जा चुका है।

किसानों को बीजों के लिए मिलेगी 80 प्रतिशत सब्सिडी

बुंदेलखण्ड में रबी की खेती तो ठीक ठाक होती है परन्तु खरीफ की फसल की खेती कम होती है। इसलिए सरकार ने बुंदेलखण्ड के किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ की फसलों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

यह सब्सिडी विशेष अनुदान के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। इसमें उन्नत, प्रमाणित तथा संकर बीजों को शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार संकर बीजों को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहती है। सब्सिडी मिलने के बाद ज्यादा क्षेत्रफल में खेती हो सकेगी। पूर्व में 8.58 लाख हेक्टेयर में होने वाली खेती को 16.02 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करने की भी योजना है।

क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा

सरकार की योजना क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा देने की भी है। 50 एकड़ के क्लस्टर पर बायो फेंसिंग कराने की योजना है, जिससे पशुओं से आने वाली दिक्कतें दूर होंगी और किसानों की आय बढ़ेगी। प्रदेश सरकार ने किसानों द्वारा क्लस्टर बनाने की दशा में दस लाख लागत तक के कृषि यंत्रों हेतु आठ लाख रूपये तक की सहायता देने का निर्णय लिया है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी